45.5 केन्द्रीय सरकार के लोक ऋण

योजनाकाल के प्रारम्भ से ही सरकार ने विकास सम्बन्धी व्यय के वित्त पोषण के लिए लोक ऋण को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। भारत सरकार का कुल आन्तरिक ऋण 1950-51 में 2,022 करोड़ रुपए (अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 22.6 प्रतिशत) से बढ़कर 1980-81 में 30,864 करोड़ रुपए तथा 1990-91 में 1,54,004 करोड़ रुपए (अर्थात् राष्ट्रीय आय का 22.7 प्रतिशत तथा 29.0 प्रतिशत हो गया)। नब्बे के दशक में आन्तरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 27 प्रतिशत से ऊपर ही रहा।[1] कुल आन्तरिक देयताएं 1990-91 में करीब 53 प्रतिशत हो गई थीं। 1990 के दशक में इसमें थोड़ी कमी देखी जा सकती

---

1 1999-2000 से आन्तरिक ऋण में अत्यधिक वृद्धि दिखाई गई है तथा लघु बचत, भविष्य निधि, आदि अन्य देयताओं में उसी अनुपात में भारी कमी। इसका कारण यह है कि लघु बचत जमा तथा लोक भविष्य निधि में से 1,80,273 करोड़ रुपए को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में बदल दिया गया है।

Scanned with CamScanner

है और यह 50 प्रतिशत के लगभग रही। लेकिन 1999-2000 से इसमें फिर वृद्धि देखी जा सकती है जो 2003-04 में 61 प्रतिशत से भी ऊपर चला गया। विदेशी ऋण में भी कमी देखी जा सकती है—1980 के दशक में 6 प्रतिशत या उससे अधिक के मुकाबले में 1990 के दशक में 5 प्रतिशत से कम। यह परिणाम उस समय प्राप्त होता है जब विदेशी ऋण को ऐतिहासिक विनिमय दर पर रुपए में परिवर्तित किया जाता है। यदि चालू विनिमय दर से ऐसे ऋण को रुपए में बदला जाए तो विदेशी ऋण नब्बे के दशक में सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत से ऊपर रहता है; 1991-92 में तो यह 18 प्रतिशत के लगभग था।

1980 के दशक के दौरान राजकोषीय घाटे में हुई तीव्र वृद्धि स्वाभाविक ढंग से केन्द्रीय सरकार की ऋणग्रस्तता के रूप में प्रदर्शित हुई। भारत सरकार की कुल देयताएं मार्च 1981 के अन्त में 59,749 करोड़ रुपए या सकल देशी उत्पाद का 44 प्रतिशत थीं। यह मार्च 1991 के अन्त तक तेजी से बढ़कर 3,54,662 करोड़ रुपए या सकल उत्पाद के 59.1 प्रतिशत पर पहुंच गयीं।

सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सरकार की कुल देयताएं (आन्तरिक + बाह्य) 1990-91 में 55.3 प्रतिशत थीं। 1996-97 में घटकर 49.4 प्रतिशत हो गईं। यह ह्रास राजकोषीय घाटे को कर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत घटाने के प्रयास का परिणाम था। सघउ के अनुपात के रूप में कुल देयताएं 2002-03 में 63.5 प्रतिशत थीं। सघउ की वृद्धि दर में तेजी आने तथा कुल देयताओं की वृद्धि गति के धीमी पड़ने के कारण सघउ के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सरकार की कुल देयताएं में क्रमिक ह्रास हुआ।

केन्द्रीय सरकार की कुल देयताओं की वर्तमान स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

केन्द्रीय सरकार की कुल देयताएं (GDP के प्रतिशत) : मार्च के अन्त में

मद (1 + 2)	2004-05	2005-06	2007-08	2008-09	2009-10 (RE)	2010-11 (BE)
1. आंतरिक देयताएं (a + b)	59.6	58.7	54.7	54.4	51.5	48.0
(a) आंतरिक उधार (i + ii)	39.4	37.6	36.3	36.3	35.7	34.7
(i) बाजार उधार तथा बॉण्ड	37.2	34.5	33.0	31.6	31.8	31.5
(ii) RBI से अर्थोपाय अग्रिम	2.2	3.2	3.3	4.7	3.9	3.3
(क) ट्रेजरी बिल	1.5	2.5	2.8	4.3	3.6	3.0
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियां	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3
(b) अन्य देयताएं, जिनमें	20.3	21.0	18.4	18.0	15.9	13.3
(i) लघु बचत	10.2	11.2	9.6	8.4	7.2	6.0
(ii) भविष्य निधि	1.9	1.8	1.5	1.5	1.4	1.3
2. बाह्य ऋण	1.9	2.6	2.4	2.2	2.1	2.1
3. सकल केन्द्रीय देयताएं	61.5	61.2	56.9	56.6	53.7	50.1

स्रोत : Government of India, *Indian Public Finance Statistics*, 2010-11, July 2011, p. 99, Table 7-2(A).

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार की सकल देयताओं के दो प्रमुख अंग हैं, यथा—(क) आन्तरिक देयताएं तथा (ख) बाह्य ऋण। आंतरिक देयताओं के भी दो घटक हैं, यथा—आंतरिक ऋण एवं अन्य देयताएं। आंतरिक ऋण के भी दो प्रमुख उपघटक हैं—बाजार उधार तथा बॉण्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम। अन्य देयताओं के दो प्रमुख उपघटक लघु बचत तथा भविष्य निधि हैं।

GDP के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार की सकल देयताएं, दो कारणों से इस सदी में घटती गयी हैं—आर्थिक वृद्धि की दर में तेजी तथा FRBM अधिनियम, 2003 के लागू होने के पश्चात ऋण की मात्रा में सापेक्ष कमी। 2002-03 में सकल देयताएं—GDP अनुपात 63.5 प्रतिशत था। यह अनुपात 2004-05

Scanned with CamScanner

में 61.5 प्रतिशत तथा 2007-08 में 56.9 प्रतिशत हो गया। सितम्बर 2008 से प्रारंभ वैश्विक वित्तीय तथा आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी 2008-09 में पड़ा। इस कारण दिसम्बर 2008 से राजकोषीय प्रेरणा के अन्तर्गत कर की दरों में कमी तथा लोक व्यय में वृद्धि की नीति को अपनाया गया। इन उपायों के कारण राजकोषीय संतुलन की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। फलतः 2007-08 के 28,37,425 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में केन्द्रीय सरकार की कुल देयताएं बढ़कर 31,59,198 करोड़ रुपए हो गयीं अर्थात् 11.3 प्रतिशत अधिक हो गई। फिर भी सापेक्ष देयताएं, अर्थात् GDP के प्रतिशत के रूप में 0.3 प्रतिशत कम ही रहीं क्योंकि आर्थिक विकास की गति चालू कीमत पर अधिक 12.9 प्रतिशत रही। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने के कारण अगले वर्षों में सापेक्ष देयताओं में और कमी आई—2009-10 में 53.7 प्रतिशत तथा 2010-11 के बजट अनुमान में 50.1 प्रतिशत। 2011-12 में राजकोषीय संतुलन की स्थिति संशोधित अनुमान में बजट अनुमान की तुलना में काफी खराब हो गई। इस वर्ष के बजट अनुमान में कुल देयताओं के GDP के 48.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था। (Economic Survey 2011-12, p. 62.) 2012-13 के बजट अनुमान में इस प्रतिशत के 45.5 रहने की उम्मीद है। तेरहवें वित्त आयोग तथा सरकारी ऋण रिपोर्ट 2010 (Government Debt Report 2010) में निर्धारित लक्ष्यों से बजट अनुमान के आंकड़े काफी कम हैं।

2012-13 के बजट के अनुसार कुल ब्याज अदायगियां (Total interest payments) जो 2010-11 में 2,34,022 करोड़ रुपए थीं, 2011-12 के संशोधित अनुमान में 2,75,618 करोड़ रुपए तथा 2012-13 के बजट अनुमान में 3,19,759 करोड़ रुपए हो गईं। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल ब्याज अदायगियां 2010-11 में 29.7 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 के संशोधित अनुमान में 35.9 प्रतिशत हो गईं। 2012-13 के बजट अनुमान में इसमें 1.7 प्रतिशत सुधार होकर 34.2 प्रतिशत पर घटकर आयेगा, क्योंकि राजकोषीय घाटा 2011-12 के संशोधित अनुमान में GDP के 5.9 प्रतिशत से घटकर 2012-13 के बजट अनुमान में 5.1 प्रतिशत हो गया।

Scanned with CamScanner